Chief Minister's Information System
Budget Announcements 2014-15

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
1	105.0.0 (2014-15) राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का एक स्तंभ बंजर भूमि विकास भी है। राजस्थान में 180 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है। वर्ष 2014-15 में समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्य के अंतर्गत 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1 हजार 392 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।	विभाग में बंजर भूमि विकास के नाम से कोई योजना संचालित नहीं। IWMP के अंतर्गत उपलब्ध 180 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने के लक्ष्य। वर्ष 2014-15 में 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4 लाख 91 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित। राशि रू. 1392 करोड़ रुपये के विरूद्ध अब तक 709.40 करोड रूपये व्यय ।	Implemented
2	349.0.0(2014-2015) करीब 8500 ग्राम पंचायतों को भी Open Defecation Free (ODF) करने की मैं घोषणा । इस वर्ष में 1000 और उसके पश्चात् आने वाले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2500 ग्राम पंचायतों को Open Defecation Free (ODF) घोषित कराने का लक्ष्य राज्य सरकार का रहेगा।	वर्ष 2014-15 में 447, वर्ष 2015-16 में 1348, वर्ष 2016-17 में 3151 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4948, इस प्रकार कुल 9894 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुकी है।	Implemented
3	39.1.0(2014-2015) पंचायतों के पास उपलब्ध TFC तथा SFC अनुदान का एक निर्धारित अंश, पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इन योजनाओं का सुनियोजित तथा कुशल तकनीकी प्रबंधन हो सके इस हेतु पर्याप्त इंजीनियर्स तथा अन्य तकनीकी स्टाफ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे और पंचायत समितियों को इन योजनाओं के संचालन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा।	जनता जल योजनाओं के समस्त व्यय का भुगतान अनुदान राशि से करने के आदेश जारी। मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 05.02.2016 के निर्णयानुसार जनता जल योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जाने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर आवश्यक कार्मिक पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दि0 17.07.2017 को बैठक आयोजित की गई जिसमें पी.एच.ई.डी. से और	Task Started, but not Completed

Chief Minister's Information System
Budget Announcements 2014-15

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
		अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु पी.एच.ई.डी. द्वारा इन पदों को पंचायती राज में Ex कैडर के पदों के रूप में स्वीकृत कराने के आदेश चाहे है। विभाग द्वारा पीएचईडी को पुन: अनुरोध किया गया है कि पीएचईडी के वर्तमान स्वीकृत पदों मे से ही कार्मिक उपलब्ध कराये जावें।	
4	47.1.0(2014-2015) जलग्रहण विभाग द्वारा भी Four waters concept के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए इस परियोजना पर 3 करोड़ 45 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।	Four Water Concept के तहत राज्य मद से राशि रू 1.55 करोड प्राप्त ।माही एवं चम्बल नदी क्षेत्र में 263 माइनर इरिगेशन टैंक के केचमेंट को उपचारित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त।249 माइनर इरिगेशन टैंक के केचमेंट की डीपीआर तैयार।झालावाड, कोटा, बांरा एवं बूदी जिलो में तैयार प्राथमिक डीपीआर हेतु राशि रू 60.67 लाख व्यय ।अब तक कुल रूपये 150.92 लाख उपयोग ।वित्तीय वर्ष 2015 16 में राशि रू 50 करोड का प्रावधान जिससे सभी 249 माइनर इरिगेशन टैंक केचमेंट क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य रखा गया है।	Implemented